क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 237, शनिवार, 22 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

घर में जबरन घुसकर सिपाही करता था महिला सिपाही से रेप, मना करने पर बच्चों को किडनैप करने की देता था धमकी

मुरादाबाद। यूपी में मुरादाबाद जिले के देहात क्षेत्र में तैनात महिला सिपाही की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने सहारनपुर में तैनात सिपाही नरेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। महिला सिपाही ने इसके लिए आईजी से गुहार लगाई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्रामीण क्षेत्र के एक थाने में तैनात महिला सिपाही ने आईजी को दिए तहरीर में बताया था कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। महिला के अनुसार उसने पुलिस लाइंस मुरादाबाद में 2009 में आमद दर्ज कराई उस समय आरआई का आरक्षी नरेंद्र वहां मुंशी के पद पर तैनात था। आरोप लगाया कि सिपाही नरेंद्र उसके ऊपर अनुचित दबाव बनाता था। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो महिला सिपाही के घर पहुंच कर आरोपी सिपाही उससे जोर जबर्दस्ती करके उसका शारीरिक शोषण करता था। मना करने पर आरोपी बच्चों को अगवा कर जान से मारने की धमकी देकर महिला सिपाही को शांत कर देता था। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2009 से लगातार आरोपी उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और परेशान कर रहा है। उसने इसकी शिकायत 14 अप्रेल व 22 मई को एसएसपी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आईजी के हस्तक्षेप के बाद सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ सिविल लाइंस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है।

शशि थरूर के मामले में स्वामी की अर्जी पर अब चार को सुनवाई

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के मामले अदालत को सहयोग करने की मांग करने वाली वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर अदालत अब 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि वे इसपर अगली तारीख को सुनवाई करेंगे। उन्होंने पुलिस से भी कहा कि वह त्रुटिपूर्ण दस्तावेज का स्पष्ट प्रति थरूर के अधिवक्ता को दे दें। मजिस्ट्रेट ने इसके साथ ही सुनवाई स्थगित कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उसके साथ 250 पृष्ठों का दस्तावेज व एक सीडी है।

प्रख्यात कवि विष्णु खरे पंच तत्व में विलीन

नई दिल्ली। प्रख्यात कवि पत्रकार एवं हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे बृहस्पतिवार को पंचतत्त्व में विलीन हो गए।नवभारत टाइम्स (जयपुर) के पूर्व संपादक श्री खरे का आज सुबह 11 बजे निगम बोध घाट के विद्युत शव दाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका बुधवार को यहां जी बी पंत अस्पताल में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया था। वह 78 वर्ष के थे।उनके अंतिम संस्कार के समय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा प्रसिद्ध लेखक एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी, नवभारत टाइम्स के संपादक मधुसुदन आनंद, साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव, हिन्दी अकादमी के सचिव जीतन राम भट्ट, जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष असग़र वजाहत, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, प्रयाग शुक्ल, विष्णु नागर, गिरिधर राठी पत्रकार राम शरण जोशी, कुलदीप कुमार समेत कई लेखक व पत्रकार मौजूद थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने हिन्दी के प्रख्यात कवि विष्णु खरे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना भारतीय साहित्य के एक युग का अंत होना है। हरिवंश ने अपने शोक संदेश में कहा कि साहित्य, सिनेमा, समाज और भाषा के गहरे जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री खरे का जाना भारतीय साहित्य के एक युग का अंत है ,भले ही उनकी पहचान हिन्दी भाषा में बनी और वे हिन्दी के कवि के रूप में मशहूर हुए, लेकिन वह सिर्फ कवि नहीं थे और उनकी दुनिया सिर्फ़ हिन्दी तक ही नहीं थी। वह हिन्दी के साथ ही चेक, जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, मराठी भाषाओं पर भी वह उतनी ही पकड़ रखते थे।

टायर फटने से खेत में जाकर पलटी बस, 5 की मौत, 25 घायल

लखनऊ, एजेंसी। यूपी के अमरोहा जिले के जोया से संभल जा रही सवारियों खचाखच भरी खटारा प्राइवेट बस शुक्रवार को पलट गई। हादसे में बस में सवार पांच लोगों की मौत हो गई और 50 घायल हो गए। घायलों में 10 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे का प्रमुख कारण बस का टायर फटना बताया गया है। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे डीएम-एसपी ने घायलों का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उधर, गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा थाना डिडौली क्षेत्र में जोया-संभल रोड स्थित तुर्की इंटर कालेज पलौला के पास शुक्रवार सुबह करीब दस बजे हुआ है। जोया से करीब 70 सवारियां लादकर संभल की ओर से जा रही प्राइवेट बस पलटकर खेत में जा गिरी। हादसे से सवारियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने पुलिस को भी बुलाया और घायलों को बस से निकला, लेकिन दो लोगों की उससे पहले ही मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुलवाकर 55 से अधिक घायलों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में तीन और घायलों ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में दम तोड़ने वाले खुर्शीद (55 साल) निवासी गांव भीकनपुर मुंडा थाना डिडौली, नयाब पत्नी गुलाम रसूल (45 साल) निवासी गांव पलौला थाना डिडौली और तहजीब पुत्र बुनियाद (15 साल) निवासी गांव हटव्वा थाना डिडौली निकले। जबकि घटनास्थल पर मरने वाले दोनों लोगों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर डीएम हेमंत कुमार, एडीएम गुलाब चंद्र, पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन टाडा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का जायजा लिया। चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए किसी भी तरह की इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़-

जिस स्थान पर हादसा हुआ, उस स्थान पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। घटना की सूचना आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना, वह घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। घायलों के परिजन और आसपास को लोग पहुंच गए। भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी लोग बस के नीचे दबी सवारियों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुराहाल है।

मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद
भीड़ ने फूंकी पुलिस जीप, दरोगा का सिर फटा

गोरखपुर। गोरखपुर के भटहट में मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद की खबर है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की एक जीप को फूंकने और चौकी में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने की सूचना मिल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। एक दरोगा का सिर फट गया है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत जुलूस में शामिल एक ताजिया के बिजली के तार से छू जाने से हुई जिसकी वजह से एक बच्चा झुलस गया। बताते है कि इस घटना के बाद कुछ लोगों ने भटहट पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। इसमें चौकी पर तैनात दरोगा दिलीप कुमार चौधरी, होमगार्ड ओमप्रकाश सिंह के सिर में चोट आई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मेडिकल कालेज से इलाज कराकर लौट रहे घुघुली के रहने वाले शिवनाथ यादव अपने चार पहिया वाहन से लौट रहे थे। घटना को देखकर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से चौकी पर पहुंचकर शरण ली लेकिन भीड़ ने वहीं पर उनकी गाड़ी तोड़ दी। चौकी पर मौजूद पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया। कई राहगीरों की भी बाइक तोड़ दी।

महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली ■ एजेंसी

यौन अपराध और महिला उत्पीड़न देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। लगातार बढ़ते जा रहे इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यौन अपराधियों का अलग डाटाबेस 'नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स' (एनडीएसओ) तैयार किया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का नौवां देश बन गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे।

गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। देश में बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और यौन अपराधों के बढ़ते मामले देश के लिए चिंता का विषय हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। डाटाबेस में ऐसे अपराधियों का फोटो, पता, डीएनए, आधार कार्ड, फिंगर प्रिंट और पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी फीड की जाएगी।

तीन श्रेणियों में बांटेंगे अपराधी

इस डाटाबेस में अपराधियों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में वह अपराधी होंगे जिन्होंने पहली बार इस तरह का अपराध किया होगा। इन अपराधियों की जानकारी 15 साल तक रखी जाएगी। दूसरी श्रेणी में शामिल अपराधियों का डाटा 25 साल तक फीड रहेदा। तीसरी श्रेणी में बार-बार इस तरह के अपराध करने वाले अपराधी शामिल किए जाएंगे। ऐसे अपराधियों का ब्योरा आजीवन डाटाबेस में सेव रहेगा।

बिना महिलाओं की भागीदारी के चुनाव जीतना असंभव : राहुल

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दक्षिणी राजस्थान के सागवाड़ा पहुंचे हैं। यहां वह राज्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर आदिवासी मतदाताओं को जनसभा करके एक बार फिर से अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसभा के लिए वह एक विशेष विमान के जरिए उदयपुर पहुंचे फिर यहां आए। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि मैं चुनाव में अधिक महिला उम्मीदवारों को देखना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना भारत में कुछ भी नहीं हो सकता।

ऐसा करने वाला दुनिया का नौवां देश बना भारत

भारत दुनिया का नौवां ऐसा देश होगा जहां इस तरह की व्यवस्था होगी। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और त्रिनिदाद व टोबैगो देशों में ऐसी व्यवस्था है। इनमें अमेरिका ऐसा देश है जहां, आम नागरिक भी डाटाबेस से जानकारी ले सकते हैं। बाकी देशों में केवल वहां की जांच एजेंसियां ही ऐसे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती हैं।

महिलाओं का हथियार है धारा 498-ए, सुरक्षा कवच प्रदान करती है यह

नई दिल्ली। हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसी में से एक है कानून की धारा 498-ए। जिसके बारे में जानकारी होना हर महिला के लिए जरूरी है। क्योंकि ये कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

क्या कहती है धारा 498-ए?

ऐसा पाया गया कि परिवार नाम के दायरे के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है। इसी के चलते महिला आंदोलन के दबाव में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 498-ए वजूद में आया। धारा 498-ए यानी किसी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालत में बचाने वाला कानून। यह कानून क्रूरता की परिभाषा भी बताता है।

क्या है धारा 498-ए?

जब आईपीसी में धारा 498-ए को शामिल किया गया था तो समाज ने, विशेषकर वैसे परिवारों ने राहत महसूस की जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ति थीं या निकाल दी गई थीं। लोगों को लगा कि विवाहिता बेटियों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वालों परिवारों में भी भय का वातावरण बना। शुरू में तो कई लोग कानून की इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे-धीरे लोग इसका सदुपयोग भी करने लगे। पर कुछ ही समय बाद इस कानून का ऐसा दुरुपयोग शुरू हुआ कि यह वर पक्ष के लोगों को डराने वाला शस्त्र बन गया।

विधायक संगीत सोम के भाई को इंस्पेक्टर ने हवालात में डाला, हंगामा

मेरठ खतौली। सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम के भाई को खतौली थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया। इसकी सूचना पर विधायक के दूसरे भाई समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और वहां थानेदार और उनमें जमकर नोकझोंक हुई। विधायक के समर्थकों ने थाने में हंगामा करते हुए थानेदार और आरोपी सिपाही को सस्पेंड करने की मांग कर दी। हंगामे की सूचना पर एसएसपी भी थाने पहुंच गए और थाने में पीएसी तैनात करनी पड़ी। गुरुवार को क्षेत्र के लाल मोहम्मद निवासी आबाद और शारिक का किसी बात पर विवाद हो गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लिया। आबाद को हिरासत में लेने की सूचना पर उसके समर्थन में सरधना विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम के छोटे भाई रिटायर फौजी गगन सोम कोतवाली पहुंचे। वह हवालात में बंद पीड़ित से मामले की जानकारी ले ही रहे थे कि पीछे से आए सिपाही ने अभद्रता शुरू कर दी। इसी दौरान कोतवाल भी पहुंच गए। कोतवाल ने विधायक के भाई गगन को हवालात में बंद करा दिया। आरोप है कि इस दौरान एक सिपाही ने उनके साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया। गगन के साथ हुई घटना की सूचना मिलने पर विधायक के दूसरे भाई सागर सोम समर्थकों के साथ खतौली थाने पहुंच गए। थाने में मौजूद थानेदार से सागर सोम की नोकझोंक हो गई। हंगामा बढ़ता देख थाने में पीएसी बल तैनात कर दिया गया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह भी यहां पहुंच गए। पीड़ित से प्रकरण की जानकारी लेने के बाद कप्तान ने घटना की सीसीटीवी फुटेज को देखा। विधायक के दोनों भाइयों से कप्तान ने बंद कमरे में वार्ता की।

कोतवाल और सिपाही पर गिर सकती है गाज

जिस तरह प्रकरण की जानकारी के बाद एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने विधायक के दोनों भाइयों से वार्ता करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को देखा, उससे कोतवाल और सिपाही पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहना संभव : एसएसपी

एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक इस प्रकरण में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने थाने की सीसीटीवी फुटेज ले ली है और इसे जांच में शामिल किया गया है।

भाई से हो गई थी नोकझोंक : संगीत सोम

विधायक संगीत सोम ने कहा है कि खतौली में उनका भाई गगन सोम रहता है, जिससे थाने में कोतवाल की नोकझोंक हो गई थी। इसकी सूचना पर ही उनके दूसरे भाई सागर खतौली थाने में पहुंचे थे। यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है।

जवान का गला रेतने में शामिल पाक सैनिकों पर करें सख्त कार्रवाई
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से कहा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हरसंभव सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू के समीप अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के एक जवान का गला काट दिया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सीमा की रक्षा कर रहे बल के शीर्ष अधिकारियों को यह संदेश दिया गया है।

घटना से जुड़े गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि मंगलवार की घटना में शामिल पाकिस्तान सैनिकों के खिलाफ हरसंभव सख्त कार्रवाई की जाए। बीएसएफ जवान का गला काटा गया था और उसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। लापता सैनिक की जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने हत्या कर दी थी। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना के खिलाफ इस तरह का पहला बर्बर कृत्य है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ जवान के शव को क्षत विक्षत करने का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि 192 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और 740 किमी लंबी नियंत्रण रेखा पर सभी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अपने एक जवान का गला रेतने के मामले में अपने पाकिस्तानी समकक्षों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और पाक रेंजर्स को कहा कि ऐसा कृत्य सैनिकों को शोभा नहीं देता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि दोपहर में फोन पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से फोन पर बात करते हुए पाकिस्तानी पक्ष ने 18 सितंबर को हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की हत्या में किसी तरह से हाथ होने से इनकार किया। भारतीय पक्ष ने इसे ऐसा कृत्य बताया है जो सैनिक को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि सूचित किया गया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बीएसएफ के जवान की गोली मारकर हत्या की है। सूत्रों ने बताया कि यह प्रतिक्रिया पाकर बीएसएफ ने अन्य पक्ष को कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर भविष्य में होनेवाली किसी भी घटना के लिए पाक रेंजर्स जिम्मेदार होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आज दोपहर दोनों पक्षों के बीच फोन पर संक्षिप्त बात हुई। जब पाकिस्तान के संज्ञान में लगाया गया कि उन्होंने बिना उकसावे के गोलीबारी करके जवान की हत्या कर दी है तो उन्होंने घटना में अपने सैनिकों का हाथ होने से साफ-साफ इनकार कर दिया है। बीते तीन दिनों में बीएसएफ ने जवान की हत्या करने और गला रेतने पर अपने समकक्षों के समक्ष दूसरी बार विरोध जताया है। यह जवान सात अन्य के साथ रामगढ़ सेक्टर में सीमा बाड़ से आगे सरकंडे काटने के लिए गए थे।

रॉफेल पर सीतारमण ने फिर झूठ बोला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विवाद को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफा मांगा। उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) की क्षमताओं को लेकर सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इससे पहले सीतारमण ने कहा था कि यूपीए के कार्यकाल में ही एचएएल को सौदे से बाहर कर दिया गया था। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग में कांग्रेस अध्यक्ष को मसखरा शहजादा कहा। उन्होंने लिखा कि राहुल के नेतृत्व में झूठ फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है।

पूर्व एचएएल प्रमुख ने रक्षामंत्री का झूठ पकड़ा- राहुल ने गुरुवार को ट्वीट किया, आरएम (राफेल मिनिस्टर) ने फिर से भ्रष्टाचार के बचाव में झूठ बोला। एचएएल के पूर्व प्रमुख टीएस राजू ने इसे पकड़ा। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट में राजू ने कहा है कि एचएएल भी राफेल विमान बना सकती है। राहुल ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया।

'गली-गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार...'

डूंगरपुर/जयपुर। राहुल ने कहा,'नरेंद्र मोदीजी ने कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, लेकिन आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली-गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रॉफेल विमान सौदे में कथित घपले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और कहा कि देश से एक नयी आवाज उठ रही है कि गली-गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मंगलवार को आरोप लगाया- सीतारमण ने कहा है कि सरकारी एचएएल के पास जेट बनाने की क्षमताएं नहीं हैं। इससे एचएएल की छवि खराब हुई है। एचएएल ने अब तक 4,060 विमानों का निर्माण किया है।

'दरबारी मसखरेबाजी' से प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं जेटली : कांग्रेस

कांग्रेस ने वित्त मंत्री जेटली के पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को 'मसखरा राजकुमार' कहने पर पलटवार करते हुये श्री जेटली को 'दरबारी मसखराबाज' करार दिया और कहा कि प्रासंगिक बने रहने के लिए वह बेकार के ब्लॉग लिख रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने श्री जेटली के नाम का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया 'हां 'जेटलाई जी', निराशा की स्थिति में बेकार के ब्लॉग लिखकर प्रासंगिक बने रहने के लिए दरबारी मसखरेबाजी करें, लेकिन कृपया यह भी बतायें। इसके बाद उन्होंने तीन सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है जब रॉफेल घपले में फँसते हैं तो अपशब्दों के पीछे क्यों छिपते हैं, एचएएल से 30 हजार करोड़ रुपये का ठेका वापस क्यों लिया और राफेल सौदे में 41 हजार करोड के नुकसान का जवाब क्यों नहीं देते हैं।

स्कूल छोड़ने का दबाव के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली। नौवीं में दो बार फेल होने पर स्कूल छोड़ने का दबाव बनाये जाने के खिलाप एक लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क है। इसपर 24 सितम्बर को सुनवाई होने की संभावना है। तुगलकाबाद के एसकेवी स्कूल म पढ़ने वाली पूजा ने अपने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दाखिल कर कहा है कि वह नौंवी में पढ़ती है और दो बार फेल हो चुकी है। उसके प्रिसपल उसपर दवाब बना रहे हैं कि वह स्कूल छोड़ दे और पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करे, जबकि वह नियमित पढ़ाई करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रिसपल ने इस तरह दवाब बनाकर नौंवीं में फेल होने वाले कई छात्राओं को स्कूल छुड़वा दिया है, लेकिन वह स्कूल नहीं छोड़ना चाहती है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है।

दखल

अपनों की जिंदगी बचाती आधी आबादी

अपनों का जीवन संवारने-सहेजने में जुटी रहने वाली महिलाएं अपनों का जीवन बचाने के मोर्चे पर भी आगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत ही नहीं दुनियाभर में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा अंगदान कर रही हैं। पुरुषों में अब भी संवदेनशीलता के पैमाने पर जागरूकता आनी बाकी है। अगर केंद्र सरकार नियमों में ढील दे और समाज में भ्रांतियों को दूर किया जाए, तो यकीनन स्थिति में बदलाव किया जा सकता है।

अपनों का जीवन संवारने-सहेजने में जुटी रहने वाली महिलाएं अपनों का जीवन बचाने के मोर्चे पर भी आगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत ही नहीं दुनियाभर में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा अंगदान कर रही हैं। सिर्फ जीवनसाथी के लिए ही नहीं, महिलाएं अपने बच्चों, भाई-बहनों या दूसरे परिजनों के लिए अंगदान करती हैं। कुछ समय पहले देश के तीन अस्पतालों (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पीजीआई चंडीगढ़ और नारायणा अस्पताल, हैदराबाद) में अंग प्रत्यारोपण और अंगदान के आंकड़ों से पता चलता है कि ऑर्गन डोनेट करने वालों में 85 फीसदी तक महिलाएं हैं। अंग का लेन-देन अगर पति और पत्नी के बीच है तो पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी देने वालों में 87 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि पत्नियों की जान बचाने में पुरुषों का प्रतिशत केवल 13 फीसदी ही है। गौरतलब है कि 1997 में ऐसे आंकड़े जुटाने वाला पहला शोध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हुआ था। उसके बाद कई अस्पतालों के अंगदान के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अंगदान करने का लगभग पूरा भार महिलाओं के ही हिस्से है। व्यावहारिक रूप से भी अपने परिवेश में गौर करें तो देखने में आता है कि अंगदान कर अपनों का जीवन बचाने में वालों में अधिकतर महिला डोनर्स ही हैं।

सुरक्षा और समानता के मोर्चे पर आज भी अपने अधिकारों के लिए जूझ रही आधी आबादी अपनों का जीवन बचाने के मोर्चे पर आगे हैं। यूं भी भारत जैसे परंपरागत समाज में तो मानो यह रीत ही है कि अपनों की दुःख तकलीफों का हल तलाशने के लिए महिलाओं की तरफ ही उम्मीद भरी नजर से देखा जाता है। तभी तो अंगदान करने के निर्णय में महिलाओं का फैसला भी अपनों की कितनी ही अपेक्षाओं तले दबा होता है। कई मामलों में तो पत्नी पर ससुराल ही नहीं मायके तक के लोगों का यह दबाव होता है कि वो अंगदान करे और अपने जीवनसाथी की जान बचाए। एक सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारी की तरह यह जवाबदेही भी आधी आबादी के हिस्से कर दी गई। यही वजह है कि जब परिवार में किसी को अंगदान की जरूरत पड़ती है तो मां, बहन, पत्नी या बेटी आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी उठा लेती हैं। विचारणीय यह है कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में विकसित देशों की स्थिति भी खास अलग नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमरीका में भी किडनी दान करने वालों में 60 फीसदी महिलाएं ही होती हैं। इतना ही नहीं दुनिया के दूसरे कई देशों में भी किडनी डोनेट करने के मामले में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कमोबेश यही है।

कहना गलत नहीं होगा कि अंगदान जैसे सार्थक और सराहनीय कार्य से महिलाओं का जज्बाती होना ही नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और आर्थिक निर्भरता का पहलू भी जुड़ा है। भारत में तो अंगदान को लेकर बनी सोच में लिंग भेद और आर्थिक असमानता जैसी वजहें भी शामिल हैं, जिनके चलते कई बार महिलाए अनिच्छा से भी ऑर्गन डोनेशन करती हैं। कितने ही सामजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक कारण है जो स्त्री-पुरुषों के बीच भेद की वजह ही नहीं अंगदान के आंकड़ों में भी स्त्री और पुरुष में भेद का कारण बन रहे हैं। कभी भावनात्मक बंधनों का हवाला देकर तो आर्थिक निर्भरता का भी दिखाकर। उनके अपने भी उनसे यही आशा रखते हैं कि वे घर के किसी सदस्य का जीवन बचाएं। ऐसे में गौर करें तो लगता है कि अंगदान की प्रक्रिया भले ही पूरी तरह चिकित्सकीय और वैज्ञानिक है, लेकिन हमारे यहां इसके पीछे समाज में मौजूद जटिल सामाजिक स्थितियां और सोच भी जिम्मेदार है। जीवन बचाने की इस जिम्मेदारी का बोझ लगभग पूरी तरह महिलाओं के ही सिर आ जाना कहीं न कहीं समाज और परिवार में आधी आबादी के उस दोयम दर्जे को सामने लाता है, जहां वे अपना मानवीय हक पाने में आज भी पीछे ही है। फैसले लेने का अधिकार आज भी उनके पास नहीं है। निःसंदेह, महिला डोनर्स की संख्या ज्यादा होने की जड़ भी समाज की सोच में ही है।

अपने परायों को नई जिंदगी देने में हम सहभागी बनें इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में आज भी अंगदान करने वाले लोग मुट्ठी भर ही हैं। बीते कुछ सालों में बदलती जीवनशैली के चलते कम आयु में कई तरह की बीमारियां दस्तक दे रही हैं। इन बीमारियों के चलते किसी महत्वपूर्ण अंग में खराबी आ जाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनमें से कुछ व्याधियों का हल केवल अंग प्रत्यारोपण है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर अंग दान करने वालों की संख्या एक से भी कम है। हालांकि, भारत में अंगदान को लेकर आमजन की उदासीनता की वजह जागरूकता की कमी ही नहीं सरकारी स्तर पर इसकी उपेक्षा किया जाना है। यही वजह है कि बीते साल जागरूकता लाने और अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने भी अंगदान करने वाले परिजनों को रियायत और प्रोत्साहन देने की बात भी कही थी। असल में देखा जाए तो अंगदान को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे प्रयास जरूरी भी हैं, क्योंकि नागरिकों की ओर से स्वैच्छिक अंगदान ही अंग प्रत्यारोपण का एकमात्र वैध तरीका है। इसका कोई और चिकित्सकीय विकल्प नहीं है। अंगदान दूसरों के लिए जीवनदान समान है। लेकिन यह भी एक कटु सच है कि आकार और आबादी के हिसाब से स्पेन, क्रोएशिया, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देश भी अंगदान में भारत से काफी आगे हैं ।

अंगदान के लिए लोगों को बार-बार प्रेरित करने व जन जागरूकता लाने वाले अभियान चलाने के बावजूद हमारे यहां अंगदान को लेकर सोच नहीं बदली है। यहां तक कि मौत के बाद भी अधिकांश लोग धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों के कारण अंगदान नहीं करते। अब इसे जागरूकता की कमी कहें या उदासीनता की प्रवृत्ति। हमारे देश में हमेशा से ही अंगों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर रहा है। जो मांग पूरी हो रही है उसमें भी ज्यादातर डोनर्स महिलाएं ही हैं। यह भी आधी आबादी पर बोझ बढ़ाने वाली बात ही है, जबकि भारत में साल 1994 में अंगदान को लेकर बना कानून भी जेंडर की कोई बात नहीं करता। अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही अंगदान कर सकते हैं। पत्नी, मां या बहन ही नहीं पति, पिता या बेटा भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। नियमों के मुताबिक भारत में प्रत्यारोपण का पूरा कार्यक्रम द ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत किया जाता है। जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अंगों को बेच या खरीद नहीं सकता। जिस इन्सान का प्रत्यारोपण होना है, अंगदान सिर्फ उसके सगे-संबंधी या बेहद नजदीकी रिश्तेदार ही कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी जांच-पड़ताल की जाती है। अंग देने का निर्णय डोनर स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के करे यह इस एक्ट का अहम नियम है। ऐसे में देखने और समझने में यही लगता है कि महिलाएं भी अपनी इच्छा से अंगदान करती हैं, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिन्होंने जीवन बचाने के इस सार्थक कार्य को भी उनके लिए बोझ और मजबूरी बना दिया है। अगर सरकार नियमों में ढील दे और समाज में भ्रांतियों को दूर किया जाए, तो स्थिति बदल सकती है। अब धीरे-धीरे अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है, मगर अभी जो औसत है, उसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

डॉ. मोनिका शर्मा
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

सेना के अधिकारों की भी सोचें हम

पिछले दिनों एक आतंकी के शव को घसीटे जाने पर मानवाधिकार संगठनों ने खूब तमाशा किया, पर अब एक जवान के साथ की कई क्रूरता पर वे खामोश हैं। सवाल है कि इन लोगों को सेना का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? क्या हमारे जवान इंसान नहीं हैं।

पिछले दिनों सेना द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मौत के घाट उतारने के बाद उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाने की तस्वीर वायरल होने के बाद कुछ मानवाधिकार संगठन और उसके लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। दलीलें ऐसी दी गईं मानों मरने वाला आतंकी नहीं महात्मा हो। सेना को खूब बुरा-भला कहा गया। सरकार तक को सामने आ कर सफाई देनी पड़ी और सेना को किए गए सलूक का कारण बताना पड़ा। बावजूद इसके वे टस से मस नहीं हुए। खैर, विवाद अब भी जारी है। मगर इस बीच सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। इसमें एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के साथ सीमा पार क्रूरता की गई और उसके शरीर को क्षत-विक्षत किया गया। सेना को जवान का शव जिस हालत में मिला, वह रोंगटे खड़े कर देता है। मगर अब तक एक भी मानवाधिकार संगठन की जुबान नहीं खुली है।

आतंकियों के नाम पर पड़ोसी मुल्क से अपनी जेबें गर्म करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को सेना का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? क्या वे इंसान नहीं हैं या फिर बॉर्डर पर मरने के लिए ही खड़े हैं। आतंकी के साथ जो सलूक किया गया था, वैसा कई देशों में किया जाता है। आतंकी के शव पर विस्फोटक बंधा होने की आशंका के चलते कुछ देर तक शव को घसीटा जाता है। बाद में उसके शव को दफन कर दिया जाता है। आतंकियों के मानवाधिकार की बात करने वाले क्या यह भूल गए कि कारगिल जंग के बाद पाककी सेना जब अपने जवानों को मरने के बाद छोड़ गई थी, तो हमारी सेना ने ही सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया था। यह सब कुछ जानते हुए आतंकी की मौत पर कोहराम मचाना और अपने जवानों की शहादत पर मौन रहना दोगली नीति का परिचायक है। इस तरह की मानसिकता देश में सौहार्द्र को कम करती है और सेना का मनोबल कमजोर करती है।

याद होगा कश्मीर में पत्थरबाजी के बीच जवानों के बच्चों ने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई थी कि क्या कश्मीर में पत्थरबाजों के ही मानवाधिकार होते हैं, सैनिकों के नहीं? बता दें कि सेना की टुकड़ी पर पत्थर फेंकने वालों पर सेना की कार्रवाई में दो नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने सेना के एक अधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सेना ने भी जवाबी एफआईआर दर्ज कराई थी। इन बच्चों ने राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू को लिखे पत्र में जवानों के मानव अधिकारों के संरक्षण की मांग की थी और पूछा था कि पत्थरबाजों पर रहम और सैनिकों पर सितम क्यों हो रहा है? इन बच्चों का तर्क था कि पत्थरबाज रोज सैनिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि हम क्यों सेना के मानवाधिकारों को लेकर मुखर नहीं हैं। क्यों नहीं आतंक परस्त बातें करने वालों पर सख्ती कर पा रहे।

जलसंकट के निदान की बात करें

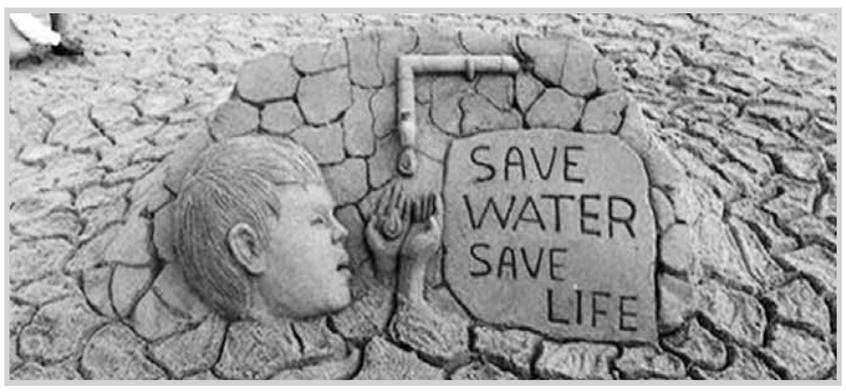

जल संकट से आज पूरी ही दुनिया जूझ रही है। कई देशों ने तो ऐसी खेती ही बंद कर दी, जिसमें पानी की खपत अधिक होती थी। हम पानी का प्रत्यक्ष कम, तो अप्रत्यक्ष इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम एक किलो गेहूं पैदा करने में 17 सौ लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के इस अप्रत्यक्ष इस्तेमाल पर वाटर फुटप्रिंट के जरिए नजर रखी जाती है।

दो आंकड़े हैं- एक वर्ष-1951 का और दूसरा वर्ष-2001 का। हमारे देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जहां वर्ष-1951 में 14 हजार 180 लीटर थी, वह अब पांच हजार 120 लीटर हो गई है। 2025 तक यह उपलब्धता घटकर करीब तीन हजार लीटर रह जाएगी। तब सवाल है कि फिर क्या होगा? दुनियाभर में कार्बन की खपत की मात्रा कितनी है, इसकी जानकारी के लिए दुनियाभर में कार्बन फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पानी की खपत कहां और कितनी हो रही है, इसे जानने के लिए आजकल एक नई अवधारणा प्रचलन में है, जिसका नाम है, वाटर फुटप्रिंट। यह बताता है कि हम अपनी जिंदगी में रोज किन स्रोतों से कितने पानी की खपत करते हैं।

मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक और पानी:-सबसे पहले हम बात करते हैं, बोतलबंद पानी की। पिछले 20 सालों में भारत में बोतलबंद पानी के व्यापार में जो तेजी आई व तरक्की हुई है, वह आश्चर्यजनक है। क्या आपको पता है कि जब आप एक बोतल पानी खरीदकर पीते हैं, तब आप उस पानी को कितनी कीमत पर खरीदते हैं व इसके साथ ही आप कितने लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। शायद, आपको यह डाटा देखकर भरोसा न हो। लेकिन यही सच है और यह सच ऐसा है, जो हमें दिनोंदिन पानी के संकट की ओर धकेल रहा है। एक लीटर बोतलबंद पानी तैयार करने में पांच लीटर पानी खर्च होता है।

एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में साल-2004 में 154 अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए 770 अरब लीटर पानी का उपयोग किया गया था। भारत में भी इसी प्रक्रिया के लिए 25.5 अरब लीटर पानी बहाया गया। यह अकारण नहीं है कि बनारस से लेकर केरल तक के गांव वाले इन बोतलबंद कंपनियों व कोला कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। कैलिफोर्निया के पेसिफिक इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2004 में अमेरिका में 26 अरब लीटर पानी की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलें बनाने के लिए दो करोड़ बैरल तेल का उपयोग किया गया। प्लास्टिक से बनी बोतलें भी भूजल को प्रदूषित करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग की भी कारण बनती हैं।

कृषि और पानी:-अब हम कुछ दिलचस्प लेकिन खतरनाक डाटा पर नजर डालते हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पूरे पानी का 90 फीसदी से भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। घरेलू उपयोग में पानी का सिर्फ पांच फीसदी ही खर्च होता है। इसके अलावा, भारत में एक किलो गेहूं उगाने के लिए लगभग 17 सौ लीटर पानी खर्च करना होता है। यानी, अगर हमारे परिवार में एक दिन एक किलो गेहूं की खपत होती है, तो हम उसके साथ लगभग 17 सौ लीटर पानी की भी खपत करते हैं। यहां तक कि जींस की जो पैंट हम पहनते हैं, उसमें भी हजारों लीटर पानी की खपत हुई होती है या फिर एक कप कॉफी के साथ हम असल में 140 लीटर पानी भी पीते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। इसे आप आभासी खपत कह सकते हैं, लेकिन यह खपत असली है।

आज मिस्र दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो गेहूं आयात करता है और चीन भी अब खाद्य उत्पादों का बड़ा आयातक बन गया है, जबकि दुनियाभर में उसके सामान बिकते हैं। सवाल है कि चीन या मिस्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब बहुत ही साधारण है। इन दोनों ही देशों ने ऐसी सभी फसलों का उत्पादन बहुत कम कर दिया है, जिनमें पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है। ये दोनों देश इस तथ्य के बावजूद ऐसा कर रहे हैं कि इनके पास पानी की फिलहाल कोई भारी कमी नहीं है और इनके पास नील और व्हांगहो जैसी नदियां भी हैं। दरअसल, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पानी बचाने के लिए हो रहा है। कोई देश पानी बचाने के लिए फसल ही न उगाए और उसकी जगह खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात करे, तो इससे समझा जा सकता है कि जल संकट को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है?

भारत के संदर्भ में देखें, तो इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल-2014-15 में भारत ने लगभग 37 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था, जबकि इतना बासमती चावल उगाने में 10 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च हुआ था। इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि भारत ने 37 लाख टन बासमती के साथ 10 ट्रिलियन लीटर पानी भी दूसरे देशों में भेज दिया, जबकि पैसा सिर्फ चावल का ही मिला। यानी, जिस देश ने हमसे चावल खरीदा, उसे चावल के साथ दस ट्रिलियन लीटर पानी मुफ्त में मिल गया या यूं कहें कि उसका इतना पानी बच गया। भारत प्रत्येक वर्ष विदेशों में लाखों टन अनाज बेचकर भारी मात्रा में पानी का आभासी निर्यात करता रहता है।

क्या है वाटर फुटप्रिंट :-यह शब्द सुनते ही सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि आखिर वाटर फुटप्रिंट है क्या? हमारे प्रतिदिन के बहुत से उत्पादों में आभासी अथवा छिपा हुआ जल शामिल होता है। उदाहरण के लिए, एक कप कॉफी के उत्पादन के लिए आभासी पानी की मात्रा 140 लीटर तक होती है। आपका वाटर फुटप्रिंट केवल आपके ही द्वारा प्रयोग किए गए प्रत्यक्ष पानी (उदाहरण के लिए धुलाई में) को ही नहीं दिखाता है, बल्कि उपभोग किए गए आभासी पानी की मात्रा को भी दर्शाता है। वाटर फुटप्रिंट इसी तरह हर उत्पाद और सेवा, जिसका हम सभी लोग उपभोग करते हैं, उसमें इस्तेमाल किए गए पानी की गणना करता है।

वाटर फुटप्रिंट हमारे सामने कई सारे सवाल उठाता है। जैसे-किसी कंपनी में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का स्रोत क्या है? इन स्रोतों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या हम वाटर फुटप्रिंट घटाने के लिए कुछ कर सकते हैं? वाटर फुटप्रिंट के तीन घटक हैं-ग्रीन, ब्लू और ग्रे। एक साथ मिलकर यही घटक पानी के इस्तेमाल की असल तस्वीर दिखाते हैं। जैसे-इस्तेमाल हुआ पानी बारिश का है, सतह का पानी है या भू-जल है। वाटर फुटप्रिंट किसी प्रक्रिया, कंपनी या क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की खपत व जल प्रदूषण को बताता है। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट मिट्टी की परत में छिपा जल है, जिसका उपयोग कृषि, हार्टीकल्चर या जंगल द्वारा होता है।

ब्लू वाटर फुटप्रिंट ग्राउंड वाटर है। इसका इस्तेमाल कृषि, उद्योग और घरेलू काम में होता है। ग्रे वाटर फुटप्रिंट ताजा जल (फ्रेश वाटर) की वह मात्रा है, जिसकी आवश्यकता प्रदूषण हटाकर जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए होती है। वाटर फुटप्रिंट का संबंध फ्रेश वाटर पर मानवीय प्रभाव और मानवीय इस्तेमाल से है। फुटप्रिंट के जरिए पानी की कमी और जल प्रदूषण जैसे मुद्दों को भी समझा जा सकता है। कई देशों ने तो अब अपने वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऐसे उत्पादों को दूसरे देशों से मंगाना शुरू कर दिया है, जिसके उत्पादन में पानी का ज्यादा खर्च होता है। तो क्या अब यह जांचने का वक्त नहीं आ गया है कि हमारा वाटर फुटप्रिंट क्या है? क्या हम भी अपना वाटर फुटप्रिंट नहीं घटाएंगे? जलसंकट खत्म करने को लेकर देश में अब तक जितने प्रयास हुए हैं, उन्हें काफी नहीं कहा जा सकता है। जल की उपलब्धता कम होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे में तब तक कोई भी प्रयास रंग नहीं ला सकता जब तक उपाय दीर्घकालीन न किए जाएं। जलसंकट को लेकर अब हमें गंभीर होना ही पड़ेगा।

राजेंद्र मिश्रा
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

सेना के मानवाधिकार को लेकर कोई बहस नहीं है। सेना को उसका काम करने की पूरी छूट है। जवानों को आतंक का सफाया करने के स्पष्ट निर्देश हैं।

निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री

जो लोग आतंकवाद के सरपरस्त बने हैं और आतंकियों के मारे जाने पर विलाप कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सेना के जवानों का भी मानवाधिकार है।

मनीष तिवारी, कांग्रेस

सत्यार्थ

वक्त के पाबंद थे गांधीजी

यह घटना उस समय की है, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गांधीजी घूम-घूमकर लोगों को स्वराज और अहिंसा का संदेश देते थे। एक बार उन्हें एक सभा में बुलाया गया। सभा का संचालन एक स्थानीय नेता को करना था। गांधीजी समय के बहुत पाबंद थे। वह निर्धारित समय पर सभा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां सभी लोग पहुंच गए हैं, लेकिन जिन नेता को सभा का संचालन करना था, वह नहीं पहुंचे हैं। सभी लोग बेसब्री से उस नेता की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह पूरे पैंतालीस मिनट बाद सभा स्थल पर पहुंचा। नेताजी ने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में भी सभा चल रही है। यह देखकर वह लज्जित हुए। मंच पर पहुंचकर उन्होंने आयोजकों से पूछा कि उनके बिना सभा कैसे प्रारंभ हुई? इस पर आयोजक कुछ नहीं बोले, लेकिन गांधीजी नेताजी के हाव-भाव से उनकी बात समझ गए। वे मंच पर आए और बोले- माफ कीजिएगा, लेकिन जिस देश के अग्रणी नेतागण ही महत्वपूर्ण सभा में पैंतालीस मिनट देर से पहुंचेंगे, वहां पर स्वराज भी उतनी ही देर से आएगा। यह सोचकर मैंने सभा शुरू करा दी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आपके देर से आने की आदत अन्य लोगों को भी न लग जाए। मेरा मानना है कि लोग एक-दूसरे की अच्छी बातें ही सीखें, बुरी नहीं। गांधीजी की बात सुनकर नेताजी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आगे से वह भी वक्त का महत्व समझेंगे और अपना हर कार्य निर्धारित समय पर करेंगे। हम भी बापू के विचारों से प्रेरणा लें और समय का महत्व समझें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह अपनी रफ्तार से निकलता ही चला जाता है।

रेनू सैनी

न्यूज

गुजरात सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा राशि दोगुनी की

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात सरकार ने गुरुवारक ो किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु और घायल होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि में आज दोगुनी बढ़ोत्तरी करने और इस योजना के तहत किसानों के पुत्रों, पुत्रियों और पत्नी को भी शामिल करने की आज घोषणा की। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नीतिन पटेल ने गुरुवारको जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब मृत्यु की स्थिति में एक लाख रूपये की जगह दो लाख रूपये तथा घायल को 50 हजार की जगह एक लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। अब तक इसके तहत पंजीकृत 7325559 किसानों के पुत्रों, पुत्रियों और पत्नी को भी इसके तहत लेने का फैसला किये जाने से अब अंदाजित करीब दो करोड़ 49 लाख लोग इसके तहत रहेंगे। सरकार की ओर से दी जाने वाली बीमा प्रीमीयम भी 30 से 35 करोड़ रुपए से बढ़ कर 70 से 80 करोड़ हो जाएगी।

त्रिपुरा: 3.26 लाख परिवारों का ग्रामीण रोजगार बढ़ाया

अगरतला (एजेंसी) त्रिपुरा सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले 3.26 लाख परिवारों को दो दिन का अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार देने की घोषणा की है, जिससे राज्य की 42 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या को लाभ होगा। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक लाख का इजाफा हो गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री जिश्नु देव वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परंपरागत तौर पर, शरद उत्सव से पहले ग्रामीण परिवारों को दो दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है। इसके लिए राज्य सरकार ने 11.55 करोड़ आवंटित किए हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए श्री वर्मा ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा आईपीएफटी गठबंधन सरकार बनी है, माकपा ने चुने हुए पंचायत के मुखियाओं को कार्य करने से रोक कर ग्रामीण इलाकों को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया है।

मुर्दाघर में रखे शव को देने के लिए मांगे रुपए

बरेली, (एजेंसी)। जिला अस्पताल में चाय-पानी के लिए पैसे मांगने की दस्तूर तो पुराना है, लेकिन अब शव देने के बदले भी पैसे मांगे जाने लगे हैं। जिला अस्पताल की मुर्दाघर में रखा शव लेने के लिए जब परिवार वाले पहुंचे तो वहां तैनात कर्मचारी ने एक हजार रुपये मांगे। इसे लेकर परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में कर्मचारी को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। बिथरीचैनपुर के तैयदपुर गांव निवासी मुकेश अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उस वक्त परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए शव मुर्दाघर में रखवा दिया गया। तेजराम का आरोप है कि मुर्दाघर पर मौजूद राशिद ने खुद को अस्पताल कर्मी बताकर एक हजार रुपए मांगे।

जेट में नहीं मिलेगा उड़ान के दौरान अब नाश्ता-खाना

नई दिल्ली, (एजेंसी) घाटे से गुजर रही देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज अपनी घरेलू उड़ानों पर यात्रियों को किसी भी तरह का नाश्ता-खाना नहीं देगी। हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान मुफ्त पानी, चाय और कॉफी पीने को मिलेगी। कंपनी यह नया नियम आगामी 28 सितंबर से पूरे देश में लागू कर देगी। जेट एयरवेज ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस फैसले के लागू होने के बाद टिकट के दाम काफी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि यात्रियों से नाश्ता व खाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सिक्किम में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे मोदी

गंगटोक (एजेंसी)। पीएम मोदी 23 सितंबर को सिक्किम के पाकयोंग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी रविवार सुबह 10:40 बजे पाकयोंग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर उतरेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर पीएम के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहेंगे। पट्टिका का अनावरण करने के बाद श्री मोदी को हवाई अड्डे के अधिकारी तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद श्री मोदी सेंट जेवियर स्कूल जाएंगे।

हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची शताब्दी

कानपुर, (एजेंसी)। नई दिल्ली से लखनऊ आ रही 2004 शताब्दी एक्सप्रेस गुरुवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के निकट हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। दरअसल, कानपुर सेंट्रल से ट्रेन निर्धारित समय 11.25 बजे रवाना हुई। ट्रेन अभी कानपुर पुल बायां किनारा से करीब 200 मीटर दूर ही पहुंची थी कि उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में एक खेत पर पंतग उड़ा रहे बच्चों का मांझा ओएचटी लाइन से उलझ गया। इस बीच ट्रेन का पिंटो भी मांझा से उलझा और तेज धमाके के साथ ओएचटी लाइन ट्रिप हो गई। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि इस घटना से ट्रेन के महत्वपूर्ण उपकरण को नुकसान पहुंचा और ट्रेन जस की तस खडी हो गयी। धमाके की आवाज से घबराए कई यात्री ट्रेन से बाहर आ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे का तकनीकी दल मौके पर पहुंचा और उसने तकनीकी खामी को दूर किया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक ट्रेन खडी रही। इस दरम्यान कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। खामी दूर करने के बाद ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हो गई।

झूठ बोलने वाले 'मसखरा राजकुमार' हैं राहुल गांधी: जेटली

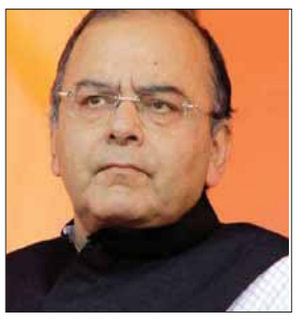

देश के 15 उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ करने वाले राहुल के बयान को जेटली ने दिया झूठा करार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा सरकार पर किये जा रहे हमले के बीच गुरुवार को उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें 'मसखरा राजकुमार' बताया और देश के 15 उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ करने उनके बयान को झूठा करार दिया।

श्री जेटली ने फेसबुक पर लिखा है कि राफेल सौदे पर उन्होंने गत 29 अगस्त को भी एक ब्लॉग लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया था। श्री गाँधी झूठ बोलने का अभियान चलाये हुये हैं। उनकी रणनीति साफ है कि एक झूठ बोलो और उसे दोहराते रहो। इससे मुद्दा-विहीन कांग्रेस को बयानों, भाषणों के लिए कुछ मनगढ़ंत मसाला मिल जाता है। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे पर उनके द्वारा पूछे गये एक भी प्रश्न का कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर नहीं दिया है। एक परिपक्व लोकतंत्र में जो झूठ पर अड़े होते हैं उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए अयोग्य माना जाता है। झूठ बोलने वाले कई लोग राजनीतिक गतिविधियों से बाहर कर दिए गए। लेकिन, यह नियम कांग्रेस जैसे'राजवंशीय संगठन'पर लागू नहीं हो सकता।

वित्त मंत्री ने राफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को पहला बड़ा झूठ और देश के 15 उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण मोदी सरकार द्वारा माफ किये जाने के आरोप को दूसरा बड़ा झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों बयानों से श्री गाँधी के झूठ का पता चलता है।

राहुल के मन में पीएम के पद का सम्मान नहीं

जयपुर ,(एजेंसी)। केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति सम्मान नहीं रखने का आरोप लगाते हुये कहा है कि गांधी परिवार का नहीं होने के कारण राहुल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते है। डूंगरपुर में आयोजित एक सभा में प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के आरोप के संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्न पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के मन प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान नहीं है क्योंकि श्री मोदी गांधी परिवार से अलग है। उन्होंने दोहराया कि श्री राहुल गांधी परिवार के प्रधानमंत्री का ही सम्मान करते है। दूसरे परिवार के प्रति उनका सम्मान नहीं है तथा वे अनर्गल बाते करते है। श्री मोदी गुजरात के एक सामान्य परिवार से संबंध रखते है जो श्री राहुल को बर्दाश्त नहीं है।

बैठक का विस्तृत एजेंडा तय नहीं हुआ, सिर्फ बैठक होगी

सुषमा-कुरैशी के बीच न्यूयार्क में होगी बैठक

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के इतर बैठक होगी जिसमें करतारपुर साहिब के लिए सिख तीर्थयात्रियों को जाने की इजाजत देने के मुद्दे पर वार्ता होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि पाक के उच्चायुक्त ने श्री खान का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र 17 सितंबर को यहां विदेश मंत्री को सौंपा था। उसी के साथ एक अन्य पत्र पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ओर से भी श्रीमती स्वराज को दिया गया था जिसमें न्यूयॉर्क में मंत्री स्तरीय बैठक का आग्रह किया गया था।

श्री कुमार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और हमने तय किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा

के वार्षिक अधिवेशन के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक होगी।

बैठक की तिथि और समय दोनों देशों के स्थायी मिशनों के द्वारा आपसी सहमति से बाद में तय किया जाएगा। इस सवाल पर कि बैठक का विस्तृत एजेंडा क्या होगा उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ बैठक होनी है, विस्तृत एजेंडा तय नहीं हुआ है।

बैठक महज़ एक मुलाकात

यह पूछे जाने पर कि भारत के पुराने रुख कि आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकता है, में कोई परिवर्तन आया है, श्री कुमार ने कहा कि यह मुलाकात महज एक मुलाकात है, इसे किसी संवाद या वार्ता की शुरुआत नहीं माना जा सकता है। बैठक में क्या बात होती है, जब तय होगा तो उसे देश के साथ साझा किया जाएगा। पाक पीएम के पत्र में दक्षेस बैठक के बारे में कहा गया है, इस बारे में पूछे सवालों के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि दक्षेस की बैठक को लेकर भारत का पुराना रुख कायम है और यह कई अन्य देशों की भी राय है कि क्षेत्र में आतंक के साये में इस मंच की बैठक के आयोजन के अनुकूल माहौल नहीं है। करतारपुर साहिब को लेकर पूछे सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि इस मुद्दे को 1999 में तत्कालीन पीएम अटलजी द्वारा लाहौर बस यात्रा के दौरान उठाया गया था जिस पर पाक ने कोई जवाब नहीं दिया था।

न्यूयॉर्क में पाक विदेश मंत्री से मुलाकात में उठेगा मुद्दा

श्री कुमार ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और उसके बाद तय हुआ कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी विदेश मंत्री से मुलाकात में इस विषय पर चर्चा होगी। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की विदेश मंत्री से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की बात पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि श्रीमती स्वराज ने श्री सिद्धू को अवगत कराया था कि श्रीमती बादल ने उनके संज्ञान में यह बात लायी है और वह इस पर पाकिस्तान से बात करेंगी। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को अगवा करके उसकी नृशंस हत्या करने और उसके शव के साथ अमानवीयता बरतने के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि इस बर्बर घटना पर बीएसएफ ने पाकिस्तान के समकक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया है। सरकार भी इसे गंभीरता से उठाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग की आतंकवाद को लेकर वैश्विक रिपोर्ट में भारत में आतंकवाद के खतरे और पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट किये जाने का स्वागत करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इससे क्षेत्र में आतंकवाद की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के दौरान बैठक का प्रस्ताव किया था। उन्होंने यह पत्र श्री मोदी के उस बधाई पत्र के जवाब में लिखा था जो उन्होंने श्री खान के प्रधानमंत्री बनने पर भेजा था। श्री मोदी ने इसमें दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की बात कही थी।

फिलीपींस में भूस्खलन: 21 की मौत, कई मलबे में फंसे

मनीला ■ एजेंसी

फिलीपींस में गुरुवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।

भूस्खलन की जानकारी मिलते ही सुरक्षाबल और राहत एवं बचावकर्मी मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के काम में जुट गए। नागा शहर के सेबू द्वीप के बाहरी इलाके में चूना पत्थर की खदान के पास बने 30 से ज्यादा घर भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आ गए जिसमें बड़ी चट्टानों और मलबे में दबे 21 लोगों को जीवित निकाल लिया गया। वहीं सात बच्चों को बचा लिया गया है। मध्य फिलीपीन्स में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई इस तरह की दुर्घटनाओं का यह ताजा मामला है। नागा की मेयर ने 64 लोगों के लापता होने की पुष्टि की। स्थानीय सरकार के प्रवक्ता गैरी काबूटाजे ने

नागा शहर के सेबू द्वीप के बाहरी इलाके में चूना पत्थर की खदान के पास बने 31 घर भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आ गए

बताया कि एएनसी राहत एवं बचावकर्मियों को इस अभियान में विशेष सावधानी बरतनी होगी। उनमें से ज्यादातर कुदाल और बेलचे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भारी उपकरणों का इस्तेमाल मलबे में दबे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चक्रवाती तूफान मैंगखूट के कारण हुई भारी बारिश से भूस्खलन की 100 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। भूस्खलन की यह ज्यादातर घटनाएं कार्डिलेरा के पहाड़ी क्षेत्र में हुई हैं। पुलिस के मुताबिक तूफान में करीब 88 लोगों की मौत हुई थी। बारिश के कारण राहत एवं बचाव अभियान में काफी कठिनाई हो रही है।

फिल्म अभिनेता मोहन बाबू की मां का निधन

तिरुपति (एजेंसी)। फिल्म अभिनेता मोहन बाबू की मां मंचू लक्ष्मम्मा (85) का गुरुवार को यहां निधन हो गया। श्रीमती लक्ष्मम्मा कुछ महीनों से बीमार थी और वे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती थी, जहां उन्होंने अंतिम सांसे ली। उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए विद्यानिकेतन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस परिसर में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। मोहन बाबू और उनका परिवार विदेश में हैं, घटना की जानकारी मिलने के बाद वे लोग यहां के लिए रवाना हो गए। विभिन्न फिल्म अभिनेताओं और राजनेताओं ने मोहन बाबू और उनके भाई रंगनाथम नायडू से फोन पर संपर्क किया और शोक जताया।

साल के आखिर तक होगा उप्र का कोना-कोना रोशन: मंत्री

लखनऊ, (एजेंसी)। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना का क्रियान्वयन उप्र में बेहतरीन तरीके से होने का दावा करते हुए केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने गुरुवार को कहा कि साल के अंत तक राज्य का कोना-कोना बिजली से रोशन कर दिया जाएगा। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रगति संतोषजनक है जिससे उत्साहित होकर केन्द्र सरकार ने यहां बिजलीकरण का लक्ष्य अगले साल मार्च से घटाकर इसी साल के अंत तक पूरा करने की ठानी है। इस दौरान बिजली से रोशन होने वाले हर गांव, तहसील और कस्बे में बाकायदा जश्न मनाया जाएगा जिसमें ऊर्जा विभाग के वाहन क्षेत्र में घूम कर विद्युतीकरण का काम पूरा होने की घोषणा करेंगे और यदि कोई घर बिजली की पहुंच से दूर रह गया हो तो उसी वाहन में आवेदन लेने का इंतजाम होगा।

येदियुरप्पा ने राजनीति में कमीशन की शुरुआत की

बेंगलुरु,(एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता बी एस येद्दियुरप्पा के आरोपों के जवाब में उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में कमीशन की शुरुआत येद्दियुरप्पा ने की।

श्री कुमारस्वामी ने कहा कि श्री येद्दियुरप्पा जिस समय सत्ता में थे उस समय उन्होंने ही राजनीति में कमीशन प्रणाली की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री येद्दियुरप्पा ने कमीशन प्रतिशत की राजनीति की शुरुआत की और अब हम पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। हम पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उम्र में मुझसे बड़ा है और एक अहम पद पर है, उसकी ओर से ऐसे आरोप लगाया जाना अनुचित है।

श्री कुमारस्वामी ने अपोलो अस्पताल में उपचार करा रहे मंत्री डी के शिवकुमार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह

कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने विस में जड़ा आरोप लगा, कहा -हम पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं

बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री येद्दियुरप्पा और उनकी पार्टी देश और राज्य की प्राकृतिक संपत्ति को लूटने में लगी हुई है।

श्री येद्दियुरप्पा ने बुधवार को मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की जनता दल (सेक्युलर)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के कामकाज पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि राज्य सरकार'कमीशन एजेंट'के रूप में काम कर रही है और रिश्वत लेकर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। पिता और पुत्र (पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगोडा और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी) मिलकर सरकार चला रहे हैं।

उत्तर कोरिया के पेकतु पर्वत (ज्वालामुखी की चोटी) पर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। इस ज्वालामुखी चोटी को उत्तर कोरिया में पवित्र माना जाता है।

सीबीआई ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, तीन से की पूछताछ

पटना ■ एजेंसी

बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के राजदार समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया वहीं समाज कल्याण विभाग के तीन अधिकारियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला

मुजफ्फरपुर में एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका अलपावास गृह यौन शोषण मामले में ब्रजेश के राजदार माने जाने वाले सुमन शाही के अलावा उसके अखबार के तीन कर्मचारी गुड्डू, विजय एवं संतोष को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के तीन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं, सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के 20 बैंक खातों को फ्रिज कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टिंग से प्रतिबंध हटा: सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध का पटना हाईकोर्ट का आदेश गुरुवार को निरस्त कर दिया। जस्टिसद्वय मदन बी लोकुर व दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के गत 23 अगस्त का आदेश यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

नोटबंदी के बाद नकदी में हुआ डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा

आरबीआई की रिपोर्ट से घिरी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नोटबंदी के मामले में सरकार को घरने के लिए हमलावर विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। क्योंकि आरबीआई के ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार के देश में नकदी की व्यवस्था को कम कर डिजिटल व्यवस्था लागू करने के दावे को गलत सिद्ध कर दिया है। दरअसल आरबीआई ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि नोटबंदी के दौरान बाजार में प्रचलित नकदी के मुकाबले मौजूदा समय में डेढ़ लाख करोड़ करेंसी ज्यादा है। इस वक्त चलन में नगद मुद्रा की संख्या 19.48 लाख करोड़ है। अब इस रिपोर्ट के बाद सरकार कैशलेस के बढ़ते प्रभाव के दावे पर घिरती नजर आ रही है।

नोटबंदी के दौरान चलन में 17.97 लाख करोड़ नकदी थी: आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने ताजा रिपोर्ट में बताया है कि नोटबंदी के समय की तुलना में मौजूदा समय में डेढ़ लाख करोड़ नकदी ज्यादा है। ये आंकड़े 14 सितंबर तक के हैं। इससे पहले 31 मार्च 2018 को ये आंकड़ा 18.29 लाख करोड़ था। जबकि नोटबंदी के दौरान देश में 17.97 लाख करोड़ नकदी थी जो कि अब डेढ़ लाख करोड़ बढ़कर 19.48 लाख करोड़ हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साप्ताहिक आधार पर करंसी में बढ़ोतरी 8300 करोड़ प्रति सप्ताह थी लेकिन सालाना आधार पर ये इजाफा 23 फीसदी है। बता दें कि आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक चलन में मुद्रा का मतलब नकदी और सिक्के दोनों शामिल हैं।

चुनाव के मद्देनजर नकदी में बढ़ोतरी-मीडिया रिपोर्ट: आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवतः नकदी में बढ़ोतरी का एक कारण त्योहारों का सीजन हो या फिर आगामी चार राज्यों में और लोकसभा के चुनाव की वजह से हो सकता है। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है इसलिए मार्केट में नगदी की मात्रा बढ़ती है। हालांकि हाल के दिनों में थोक और खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें खासकर डीजल की बढ़ी कीमतें महंगाई को बढ़ावा दे रही है।

तीन तलाक — दंडनीय अपराध बनाने वाले बिल को कानून के रूप में राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

यूपी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, सबसे कम दिल्ली में

नई दिल्ली ■ एजेंसी

अब एक साथ तीन तलाक देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में गैरकानूनी घोषित किए जा चुके तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) को दंडनीय अपराध बनाने वाले बिल को कानून के रूप में मंजूरी देने वाले अध्यादेश पर बुधवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए।

इससे पहले सुबह केंद्र सरकार ने इसे अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी दे दी थी।

उप्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 126 मामले आए

सरकार के मुताबिक, तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश सामने आए हैं। यूपी में जनवरी, 2017 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिए जाने तक 126 और इसके बाद से अब तक 120 मामले सरकार के संज्ञान में हैं।

तीन तलाक अपराध बना तो लोग शादी करने से डरेंगे- शाइस्ता अम्बर

इस अध्यादेश को लेकर देश के कानूनविदों और मजहब के जानकारों से बात की और इस संबंध में उनकी राय जानने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर का कहना है कि इस कानून से पति-पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। कानून ऐसा बने जो शरीयत से न टकराए। तलाक सामाजिक बुराई है, इसे अपराध बनने से लोग शादी करने से डरने लगेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी का कहना है कि केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को आधार बना रही है वह दो जजों का अल्पमत वाला फैसला था। बोर्ड अभी इस अध्यादेश पर निगाह बनाए हुए है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। वहीं तलाक मामलों के जानकार एडवोकेट अमीर अहमद का कहना है कि तीन तलाक एक सामाजिक बुराई है।

कानून को आधार बनाकर अदालत जा सकती हैं पीड़िताएं: गर्ग

सुप्रीम कोर्ट के वकील डी. के. गर्ग का कहना है कि तीन तलाक से पूर्व में सताई गई महिलाएं सरकार के कानून को आधार बनाकर इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

स्मार्ट सिटी का कड़वा सच

मस्कती हॉस्पिटल तथा मल्टिलेबल पार्किंग के शौचालयों में लगा ताला

महिला प्रसाधनों में नहाते है कर्मचारी

सूरत। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाली सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित मस्कती हॉस्पीटल तथा उसके ठीक सामने निर्मित मल्टीलेबल पार्किंग के पुरुष शौचालयों में ताले लगे होने तथा महिला प्रसाधन घरों में पुरुषों के नहाने के कारण आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

क्रांति समय के संवाददाता ने जब सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित मस्कती हॉस्पीटल तथा उसके ठीक सामने बने मल्टीलेबल पार्किंग के महिला एवं पुरुष शौचालयों तथा प्रसाधन घरों की पड़ताल की तो वहा तमाम प्रकार की अनियमितताए पाई गई। एक तरफ जहां मस्कती हॉस्पीटल के शौचालयों तथा प्रसाधन घरों में ताला लटका हुआ मिला वहीं मल्टीलेबल पार्किंग में निर्मित महिला प्रसाधन घर में पुरुष कर्मचारियों को नहाते हुए पाया गया। मनपा द्वारा संचालित ऐसे महत्वपुर्ण स्थलों पर इस प्रकार की अव्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि मनपा प्रशासन नागरिक सुविधाओं को लेकर अत्यंत ही लापरवाह है। शहर की स्वच्छता तथा नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा झटका लग रहा है। नागरिक सुविधाओं के नाम पर कई बार राष्ट्रीय पुरुस्कार से सम्मानित मनपा के इस रवैये को लेकर आम जनता में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि जब आम लोगों के लिए मनपा समुचित व्यवस्था नहीं कर सकती तो उसे स्मार्ट सिटी होने का ढिंढोरा पीटना छोड़ देना चाहिए।

सूरत में स्मृति इरानी को दिखाया काला झण्डा

सूरत। जीएसटी क्रेडिट लैप्स के विरुद्ध संहर्ष कर रहे सूरत के बुनकरों ने शुक्रवार को केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी के सूरत आगमन पर काला झण्डा दिखा कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर की दोपहर स्मृति इरानी को काला झण्डा दिखाने पर खटोदरा पुलिस ने बुनकर अग्रणी अशोक जीरावाला, मयुर गोलवाला, विजय मंगुकिया, निरव सभाया सहित चार लोगों को हिरासत में ले लिया

स्मृति इरानी सूरत में सिथेटक्स रेयान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आई थी।

बुनकरों द्वारा सूरत में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के विरोध प्रदर्शन किए जाने पर कार्यक्रम के आयोजक तथा चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारी असमंजस की स्थिति में आ गए।

मछुआरों के उत्कर्ष के लिए गुजरात सरकार कटिबद्धः मुख्यमंत्री

पोरबंदर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पोरबन्दर में समस्त खारवा जाति द्वारा आयोजित श्री रामदेवजी महाप्रभु के प्रागट्य महोत्सव समारोह में कहा कि गुजरात सरकार एक मछुआरों के उत्कर्ष के लिए कटिबद्ध है। इसलिए ही सागरखेड़ वेट मामले में तत्काल निर्णय लेकर 350 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की थी जो तय समय सीमा में ही मिली। उन्होंने कहा कि जब कोई मछुआरा समन्दर में जाता है और लौटकर नहीं आता तो उनके परिवारजनों को दस वर्ष तक भी मिलने योग लाभ नहीं मिलते थे लेकिन राज्य सरकार ने संवेदनशीलता से निर्णय लिया और अब ऐसे मामले में मिलनेपात्र सरकारी रकम एक वर्ष के अन्दर मिल जाती है। चक्रवाती तूफान के समय मछुआरों को 2 लाख रुपए बीमा राशि का कवच दिया जा रहा है। राज्य के मचुआरों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार लगातार कार्यरत है। समग्र समुद्री बेल्ट को शामिल करते हुए भावनगर-सोमनाथ-पोरबन्दर और पोरबन्दर द्वारिका कोस्टल बैल्ट का भी नेशनल हाईवे द्वारा 6000 करोड़ खर्च से फोरलेन का कार्य जारी है। इसके पूर्ण हो जाने केबाद रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर बढ़ेंगे।

विजय रूपाणी ने कहा कि रामदेवजी महाप्रभु हमेशा तमाम लोगों के कल्याण और हिन्दु समाज की संस्कृति उजागर करने के लिए सतत कार्यरत रहे और हम सभी के प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्हें कोटि-कोटी वन्दन है। भारी तादाद में उपस्थित खारवा समाज को स बोधित करते हुए रूपाणी ने कहा कि यह समाज निडर है और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। इस समाज ने समन्दर के तटों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

सूरत। महाकाल ग्रुप और क्रांति समय दैनिक समाचार महादेव नगर उधना में भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में नगरवासियों और गणेश भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

एक लाख वेतन में कोई राजनीतिक नेता सेवा नहीं कर सकता : अल्पेश ठाकोर

अहमदाबाद। ओबीसी नेता और कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने विधानसभा सदस्यों के वेतन में 45 फीसदी बयान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विधायकों को इसकी जरूरत थी और एक लाख रुपए के वेतन में कोई भी राजनीतिक नेता सेवा नहीं कर सकता। बता दें कि 19 सितंबर को समाप्त हुए गुजरात विधानसभा के दो दिवसीय मानसूत्र के अंतिम दिन राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 45000 रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। महंगाई के नाम पर सरकार को आए घेरते विपक्ष के विधायकों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया और वेतन वृद्धि का विधेयक एकमत से विधासनभा में पारित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायक प्रताप दूधात को छोड़ अन्य किसी विधायक ने वेतन वृद्धि का विरोध नहीं किया। जबकि कांग्रेस विधाय अल्पेश ठाकोर ने तो वेतन वृद्धि को जरूरी बताया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पेश ठाकोर ने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया वेतन वृद्धि का उन सभी विधायकों ने एकमत से पारित किया जो सदन के बाहर विरोध कर रहे थे।

गणपति बप्पा मोरिया.....

नंदनवन-3 वेसू सूरत।

कैलाश नगर पांडेसरा सूरत।

अष्ठविनायक ग्रुप उमिया नगर नवा गाम डिंडोली।

शिद्धी विनायक ग्रुप प्रियंका टाउन डिंडोली।

सहानी ग्रुप नवा गाम डिडोली।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com